किसान सम्मान वर्ष में भावांतर योजना में यह कैसी अव्यवस्था

किसान सहकारी समितियों के चक्कर काट रहा , जवाबदेही पर खड़े हुए सवाल, खरीदी शुरुआत ही सवालों में, सुधार नहीं हुआ तो योजना से उठेगा विश्वास

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। केन्द्र हो या राज्य सभी सरकारों के नुमाइंदे अपने आप को किसान हितैषी होने का दम भरते है। मध्यप्रदेश में तो वर्ष 2026 को मध्यप्रदेश सरकार किसान सम्मान वर्ष के रूप में मना रही है लेकिन ये बात समझ से परे है कि किसानों का सम्मान हो रहा है या शोषण, कि जहां पर प्राकृतिक मार को झेलते हुये किसी तरह बची खुची फसल किसान अपने घर लाने में सफल हो पाये है।

अब उसे बेंचने के लिये सरकार की योजना में व्याप्त अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड रहा है यानि किसान अपनी उपज को भी बेंचने के लिये भी दर दर की ठोकरे खाता फिर रहा है कुल मिलाकर किसानों के बारे में लछेदार भाषण देने वाली सरकार के दावों की खुलेआम पोल खुल रही है।

खरीदी में देरी का सबसे बड़ा असर सहकारी समितियों (खरीदी केंद्रों) पर दिखाई दे रहा है। किसानों की भारी भीड़, अव्यवस्थित प्रबंधन और जगह की कमी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। किसान 2 से 6 दिनों तक अपनी उपज लेकर केंद्रों पर डटे रहने को मजबूर हैं ठहरने की व्यवस्था, न भोजन की समुचित सुविधा खरीदी केन्द्रो में उपलब्ध है। खरीदी केंद्रों पर उपज पहुंचने के बाद भी तुलाई समय पर नहीं हो पा रही। किसान दिन-रात अपनी बारी का इंतजार करता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। यह देरी केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं, बल्कि किसान के समय और श्रम की अनदेखी है।

भुगतान अटका, कर्ज की मजबूरी - फसल बिकने के बाद भी भुगतान समय पर नहीं मिल पाता। ऐसे में किसान को घर-परिवार की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और बेटियों के विवाह जैसे दायित्वों के लिए बाजार से उधार लेना पड़ रहा है। यह स्थिति उसे धीरे-धीरे कर्ज और आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है। वहीं खरीदी केंद्रों पर खुले में रखे अनाज पर मौसम का खतरा बना रहता है। बारिश, आंधी या तूफान आने पर फसल खराब हो जाती है और उसका सीधा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है।

खरीदी केन्द्रों में तारीखों का खेल, मूलभूत सुविधाएं नदारद

गेहूं और चना खरीदी 26 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन इसे पहले 7 अप्रैल और फिर 15 अप्रैल तक टाल दिया गया। 27 अप्रैल तक भी बड़ी संख्या में किसान वेरिफिकेशन प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। योजना कागजों में शुरू जरूर हुई, लेकिन जमीन पर उसका क्रियान्वयन अधूरा और अव्यवस्थित नजर आ रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यही है नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा?

वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सैटेलाइट डेटा और अधिकारियों के सत्यापन के बीच टकराव सामने आ रहा है। पटवारी और तहसीलदार द्वारा की गई गिरदावरी को सैटेलाइट डेटा चुनौती दे रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है। जब अधिकांश फसल कट चुकी है, तब सैटेलाइट से सत्यापन करना वैज्ञानिक दृष्टि से भी संदेहास्पद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रक्रिया फसल खड़ी होने के समय ही अधिक सटीक हो सकती थी। अब यह सत्यापन कई मामलों में अनुमान जैसा प्रतीत हो रहा है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि किसान के पास अब अपील करने का समय भी नहीं बचा। अंतिम समय में लिए गए निर्णयों के कारण उसे मजबूरी में गलत सत्यापन भी स्वीकार करना पड़ सकता है। आज किसान के मन में एक ही प्रश्न है कि यदि प्रक्रिया में देरी हुई, सत्यापन में भ्रम हुआ और भुगतान अटका, तो इस पूरी अव्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? और हर बार इसका खामियाजा केवल किसान ही क्यों भुगते? यदि समय रहते इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो भावांतर जैसी योजनाएं किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि अविश्वास का कारण बन जाएंगी।

युवाओं के लिए रोजगार देने आज मोहन्द्रा में रोजगार मेले का आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन की आजीविका मद के अंतर्गत विभिन्न वन परिक्षेत्रों में ग्राम वन समितियों के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में वन परिक्षेत्र मोहन्द्रा में पिछले चार माह के दौरान सैंपलिंग टेलर एवं असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट ट्रेड में प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनका संचालन देश की प्रतिष्ठित संस्था कैरियर पॉइंट लिमिटेड द्वारा किया गया। दोनों ट्रेड में 30-30 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जिनमें ब्यूटी थेरेपिस्ट बैच में 90 प्रतिशत से अधिक तथा सैंपलिंग टेलर बैच में लगभग 80 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के उपरांत 28 अप्रैल को प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट के साथ-साथ एक रोजगार मेले (जॉब फेयर) का आयोजन भी किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में कैरियर पॉइंट लिमिटेड द्वारा न्यू ज़ील फैशनवियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहभागिता की गई है, जिसके माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चयनित प्रतिभागियों को लगभग 16,000 से 17,000 प्रतिमाह तक वेतन मिलने की संभावना है। यह रोजगार मेला दिनांक 28 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक जनकपुर रोड, मध्य भारत ग्रामीण बैंक के ऊपर, मोहन्द्रा में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल वन विभाग के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए, बल्कि क्षेत्र के अन्य इच्छुक युवाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

ईव्हीएम वेयरहाउस का किया मासिक निरीक्षण

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस मौके पर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर देखीं व्यवस्थाएं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को देवेन्द्रनगर एवं गुनौर क्षेत्र के विभिन्न गेहूं उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा शासन के निर्देश मुताबिक सभी केन्द्रों पर किसानों के लिए आवश्यक मूलभूत प्रबंध सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं तथा आगामी दिवसों से स्लॉट बुकिंग व्यवस्था तथा उपार्जित स्कंध के भुगतान के कार्य में तेजी लाने के संबंध में आश्वस्त किया। जिला कलेक्टर ने सायलो जिगदहा उपार्जन केन्द्र सहित पाठक वेयरहाउस सिली गुनौर, पैक्स गोदाम सुंगरहा एवं बागरी वेयरहाउस अमरी के गेहूं उपार्जन केन्द्र देखे। कलेक्टर श्रीमती परमार ने खरीदी केन्द्रों पर गर्मी के मौसम के दृष्टिगत पेयजल एवं छाया संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया तथा आवश्कता मुताबिक टेंट लगवाने एवं बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान केन्द्र पर उपस्थित किसानों से उपार्जन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को समय पर तुलाई और भंडारण इत्यादि की समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश दिए।

पन्ना टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग ने किया बाघ का सफल रेस्क्यू

तीन हाथियों की मदद से बाघ को पिंजरे में रखकर मुकुंदपुर जू सतना के लिए भेजा गया

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। दिनांक 26 अप्रैल को प्रातः 06 बजे वन विभाग को ग्रामीणों की ओर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तारा में एक बाघ द्वारा मवेशियों का शिकार किया गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग का स्टाफ तत्काल मौके पर पहुँचा, जहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर बाघ की मौजूदगी की पुष्टि हुई।

बाघ की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों में व्याप्त भय एवं रोष को देखते हुए वन विभाग के अमले ने तुरंत स्थिति को संभाला। उपस्थित जनता को बाघ से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई और भीड़ को नियंत्रित कर एक सुरक्षित घेरा बनाया गया ताकि कोई जनहानि न हो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू दल एवं हाथियों को मौके पर बुलाया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व से आए दल और पशु चिकित्सक ने तीन हाथियों की मदद से बाघ की घेराबंदी शुरू की। शाम 4 बजे बचाव दल द्वारा बाघ को सुरक्षित रूप से बेहोश किया गया। शाम 05 बजे बाघ को सुरक्षित पिंजरे में लेकर उचित गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस संपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकुंदपुर जू सतना की पशु चिकित्सक टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सलेहा में स्लॉट बुक होने के बाद भी नहीं हुआ कार्य प्रारंभ

नवभारत न्यूज

सलेहा, 27 अप्रैल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए रवि की फसल के लिए खरीदी केंद्र का कार्य प्रारंभ किया गया है। लेकिन सलेहा खरीदी केंद्र में आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। सलेहा क्षेत्र के किसानों द्वारा जानकारी देते हुए बताया की कृषि उपज मंडी प्रांगण सलेहा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खरीदी कार्य किया जाना है।

जिन किसानों की 23 अप्रैल एवं 25 अप्रैल की थी उन किसानों को आज तक यह मालूम नहीं कि सलेहा में खरीदी केंद्र कब से प्रारंभ होना है। स्लॉट बुक होने का समय

भी व्यतीत हो चुका है ,लेकिन अभी तक यहां खरीदी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जिससे हजारों किसान प्रतिदिन कृषि उपज मंडी प्रांगण सलेहा खरीदी केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध की जानकारी ना तो प्रशासन की तरफसे मिल पा रही है कि सलेहा का खरीदी केंद्र कब से प्रारंभ होगा। सिर्फऑनलाइन स्लॉट बुक करने का कार्य कुछ दिन हुआ है, इसके बाद वह भी प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। साथ ही भीषण गर्मी में किसान दर-दर भटकने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि जब जिले में खरीदी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही स्लाइड भी बुक कर ली गई है तो उन किसानों की फसल का खरीदी कार्य शीघ्र किया जाए। किसानों का कहना है कि हमारे जीवकोपार्जन का साधन सिर्फ फसल है और उससे हमारे दैनिक कार्य होते हैं। वर्तमान समय में वैवाहिक सीजन होने के चलते सभी किसानों को पैसे की आवश्यकता है ।अगर खरीदी कार्य नहीं किया गया तो किसानों को व्यापारियों के यहां मन- माने दर से बेचने के लिए विवश होना पड़ेगा। क्षेत्रीय किसानों ने शासन से मांग की है कि जब खरीदी केंद्र जिले में प्रारंभ कर दिए गए हैं तो सलेहा में ही खरीदी केंद्र अति शीघ्र प्रारंभ किया जाए । जिससे किसानों को उनकी उपज का सही भुगतान समय से प्राप्त हो सके।

ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विवि ने नशा मुक्ति प्रदर्शनी का किया आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पन्ना द्वारा स्थानीय छत्रसाल पार्क में पिछले 6 दिनों से आध्यात्मिक चरित्र निर्माण एवं नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से संस्थान के सेवाधारी भाई-बहन आम जनमानस को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें एक स्वस्थ व व्यसनमुक्त जीवन जीने की राह दिखा रहे हैं।

प्रदर्शनी के दौरान उपस्थित जनसमूह को चित्रों के माध्यम से समझाते हुए संस्थान की बहन जी ने कहा कि मानव जीवन अत्यंत अनमोल है, इसे नशे की भेंट चढ़ाकर बर्बाद न करें। उन्होंने नशे के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर प्रहार करते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 200 रुपये नशे पर खर्च करता है, तो महीने के 6000 रुपये व्यर्थ चले जाते हैं।

यह धन न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाता है, बल्कि शारीरिक व्याधियों और पारिवारिक कलह का मुख्य कारण भी बनता है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे विश्व को क्षति पहुँचाता है।

सैकड़ों लोगों ने भरा संकल्प पत्र - प्रदर्शनी देखने पहुँच रहे नागरिकों ने स्वेच्छा से संकल्प पत्र भरकर भविष्य में किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करने की प्रतिज्ञा ली। ब्रह्माकुमारी विद्यालय से जुड़े भाई-बहन निरंतर लोगों के बीच जाकर उन्हें आध्यात्मिक जागृति के जरिए व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

नकाबपोश बदमाशों ने चाकू अड़ाकर महिला के गले से लूटी सोने की चेन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। पन्ना में नकाबपोश बदमाशो ने फिर एक घटना को अंजाम दिया है जिसमें शाम को टहलने निकली महिला के गले की चैन लूट कर फरार हो गये। उक्त घटना गत रविवार शाम को पन्ना नगर के पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र में सामने आई है, जहां बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की गर्दन पर चाकू रखकर उनके गले से सोने की चैन छीन ली और फरार हो गए।

शाम को टहलने निकली महिला के गले की चेन लूट कर फरार हो गये

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुरुषोत्तमपुर स्थित जगन्नाथ कॉलोनी की निवासी स्वाति तिवारी रोज की भांति शाम को ईवनिंग वॉक पर गई थीं। जब वह पेट्रोल पंप के पास स्थित रघुलीला गार्डन से वापस अपने घर की ओर लौट रही थीं, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए। बदमाशों ने महिला को रोककर उनकी गर्दन पर चाकू अड़ा दिया और दहशत फैलाते हुए उनके गले से सोने की चौन खींच ली। पीड़िता ने बताया कि दोनों आरोपी हेलमेट पहने हुए थे, जिसके कारण उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देखे जा सके। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से अजयगढ़ चौराहे की ओर भाग निकले। घटना के तुरंत बाद महिला ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचित किया और अपने परिजनों को भी जानकारी दी।

पुलिस जांच और सीसीटीवी का पेंच

सूचना मिलते ही पुलिस सब इंस्पेक्टर मनोरमा मौर्य, प्रधान आरक्षक तोमर और प्रधान आरक्षक आईमत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की। जांच के दौरान पता चला कि प्राइवेट कैमरों में फुटेज धुंधले होने के कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है, वहीं नगर में लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरों का टेंडर समाप्त हो जाने के कारण वे काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पुलिस को आरोपियों का सुराग लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर मामले की सूक्ष्मता से जांच करने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

पंचायत एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत की फेटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

एक जनवरी 2026 की संदर्भ तारीख के आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। फेटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जून को किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति और जिला स्तरीय प्रशिक्षण 27 अप्रैल तक किया जाएगा। फेटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 15 मई 2026 को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 25 मई तक ली जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 30 मई तक किया जाएगा। फेटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 18 जून 2026 को किया जाएगा।

जंगल से लेकर गांवों तक फैली महुआ की सुगंध, महुआ बीनने लोग करते हैं रतजगा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। इस समय पर जंगल व ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ के फूलों की सुगंध चारों तरफ फैलने लगी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पुरुष सुबह 4 बजे से उठकर महुआ बीनने जाते हैं।

पन्ना जिले के कल्दा पठार, पवई क्षेत्र के शिकारपुरा, बिरसिंहपुर, झांझर, हड़ा, पन्ना के खजुरी, दलहान चौकी, विश्रामगंज घाटी, मड़ला घाटी, जनवार, मनौर, जरधोवा, तालगांव, मनकी, कटरिया, पाठा, जमुनहाई, रहुनियां, इमलोनियां, पनारी, सिमरिया, रमखिरिया, लुहरहाई, सिलधरा आदि सभी जंगलों में इस समय पर महुआ बिनाई चल रही है। मालुम हो कि प्राचीन समय से लेकर आज तक वनांचल व दूर दराज गांवों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग वनोपज पर ही मुख्य रूप से आश्रित रहते हैं। वनोपज में हर्र, बहेरा, आंवला, चिरौंजी, गोंद व लाख तो है ही महुआ आदिवासियों की जीविका का मुख्य साधन है। महुआ को बीनने के बाद लोग उसे घरों में सुखाते हैं उसके बाद महुआ के अंदर भरे जीरे को कूट, फटककर खाने योग्य बनाते हैं। ताजे बीने व सूखे हुए महुआ की गर्मी सीजन में डुभरी बनाकर खाते हैं डुभरी में सत्तू डालने से उसका जायका कुछ और ही अधिक बढ़ जाता है। डुभरी का सेवन अधिकांशतः प्रथम पहर अर्थात् सुबह के समय ही करते हैं। महुआ से ठंडी के दिनों में लाटा व मुरका भी बनाया जाता है जो बहुत ही पाचक व औषधीय होता है। महुआ का उपयोग खाद्य पदार्थ के अलावा पेय पदार्थ में भी किया जाता है। महुआ से देशी शराब बनती है जिसे आदिवासी लोग सालभर अपने घरों में बनाकर पीते हैं।

रंगाई, पुताई व मरम्मत के अभाव में दूर से ही समझ में आते हैं सरकारी भवन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 27 अप्रैल। कई सरकारी भवन एवं आवासों की हालत को देखकर कोई भी कह सकता है कि इन भवनों की न तो कोई मरम्मत होती और न ही कोई रंग रोगन। भले ही ऐसे भवनों की जिमेदारी किसी भी विभाग के पास हो किन्तु इनके रख रखाव के नाम पर खानापूर्ति ही होती है। अधिकांश शासकीय विभागों के भवन एवं आवास लोक निर्माण भवन/सड़क संभाग के अंतर्गत आते हैं।

यह विभाग भवन व सड़कों के निर्माण से लेकर उनके रख रखाव का विशेष अनुभव भी रखता है। किन्तु उस अनुभव का सदुपयोग नहीं होता बल्कि दुरूपयोग ही होता है। यही कारण है कि कई ऐसे शासकीय आवास हैं जो कई वर्षो से खण्डहर में तब्दील हो चुके हैं। यदि उनका रखरखाव किया जाता तो शायद वे इस हालात में नहीं पहुचते।

खर्च होता है करोड़ों का बजट, फिर भी स्थिति दयनीय क्यों?:- जारी होने वाली निविदाओं और स्वीकृत होने वाले टेण्डरों के आधार पर यदि पता लगाया जाय तो यही जानकारी प्राप्त होगी कि सरकारी आवासों व भवनों की मरमत के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों की राशि खर्च हो रही है। विभाग से रख रखाव के नाम पर आवंटन भी प्राप्त कर लिया जाता है किन्तु टेण्डर फिक्सिंग का खेल इस तरह से हो जाता है कि ठेकेदार व अधिकारी फर्जी रिकार्ड तैयार कर समूची राशि डकार जाते है। यही कारण है कि कोई भी सरकारी आवास दूर से ही समझ में आ जाता है, उसकी जर्जर होती भौतिक स्थिति इसका सबसे बड़ा सबूत होती है। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह भी है कि प्रशासन के अधिकारियों की यह सब दिखाई नहीं देता। इसलिये इस तरह के मामलों की समीक्षा भी कभी नहीं होती।

पर्याप्त सरकारी भवन नहीं, फिर भी रख-रखाव में मनमानी:- जिला व संभागीय मुख्यालय में पर्याप्त मात्रा में सरकारी भवन भी नही हैं। इसके बाद भी लोक निर्माण सीमित भवनों के बाद भी प्राथमिकता के साथ मरमत व सुधार नहीं कर पाता। कई ऐसे सरकारी भवन हैं जहां रंगाई पुताई के नाम पर कई वर्षो से काम नहीं हुआ होगा भले ही कागजों में लाखों की राशि खर्च हो चुकी हो। लिहाजा आवश्यकता इस बात की है एक बार सभी शासकीय आवासों का भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिये। उनकी भौतिक स्थिति की जानकारी संकलित की जानी चाहिये। इसके साथ ही वर्तमान व पूर्व के वर्षो में उन भवनों के रख रखाव में जो राशि व्यय की गई उसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

करोड़ों के जारी होने वाले टेण्डरों की जांच जरूरी

कई बार जब टेण्डर प्रकाशित होते हैं देखा जाता है कि कई शासकीय आवासों का उल्लेख किया जाता है। कहीं मरमत, कहीं विशेष मरम्मत तो कहीं रंगाई पोताई के नाम पर करोड़ों के कार्य जारी होते रहते हैं। मरमत का मतलब जहां सामान्य सुधार किया जाना हो, विशेष मरमत का मतलब जहां विशेष कार्य किया जाना हो, फिर उसी के अनुसार प्राकलन में राशियों का भी निर्धारिण किया जाता है। जहां भवन किसी खास अधिकारी का होता है वहां इस तरह के कार्य बार-बार होते रहते हैं जबकि अन्य भवनों के लिये कोई प्राथमिकता ही निर्धारित नहीं होती। लिहाजा जिन शासकीय भवनों व शासकीय आवासों के संबंध में वहां के कार्यालय प्रमुख या उसमें निवास करने वाले कर्मचारी द्वारा सुधार के लिये कोई प्रयास नहीं होते वहां लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री, सहायक यंत्री कभी झांकने तक नहीं जाते।

सभी को अपनी-अपनी चिन्ता

सरकारी आवासों की बात की जाय तो सभी सक्षम अधिकारियों को केवल अपनी-अपनी चिन्ता होती है। जो यह चाहते हैं कि उनके बंगले की मरमत होती रहे, रंग रोगन होता रहे, जैसा वे चाहते हैं उस तरह से वहां काम लोक निर्माण विभाग करता रहे। शेष कहीं हो या नहीं इसकी कोई चिन्ता नहीं होती। यही कारण है कि मरमत के मामले में लोक निर्माण विभाग भी उन्हीं अधिकारियों के आदेशों का पालन करता है। जबकि शेष कार्यो में कागजी खानापूर्ति कर बंदरबांट कर लिया जाता है। इसलिये भवन मरमत व रंगाई पुताई के मामले की यदि जांच हो जाय तो अनियमितता का बड़ा मामला प्रकाश में आ सकता है।